Central Water Commission
Water Systems Engineering Directorate
******

West Block II, wing No- 5
R K Puram, New Delhi-66
Dated 27.11.2018

Subject: Submission of News Clippings

The News Clippings on Water Resources Development and allied subjects are enclosed for perusal of the Chairman, CWC, and Member (WP&P/D&R/RM), Central Water Commission; the soft copies of clippings will be uploaded on the CWC website.

27/11/2018

Encl: As above.

SPA (Publicity)

for

O/C

Deputy Director, WSE Dte.

27/11/18

Director, WSE Dte.

27/11

For information to:

Chairman, CWC, New Delhi

Member (WP&P/D&R/R.M.), CWC and all concerned, uploaded at www.cwc.gov.in

News item/letter/article/editorial Published on 27.11.2018 in the

Hindustan Times	Hindustan (Hindi)	Deccan Chronicle
Statesman	Nav Bharat Times (Hindi)	Deccan Herald
The Time of India (New Delhi)	Punjab Keshari (Hindi)	The Times of India (A)
Indian Express	The Hindu (New Delhi)	Business standard
Tribune	Rajasthan Patrika (Hindi)	The Economic Times ✓

and documented at Bhagirath (English) & Publicity Section, CWC

Kant: Water Management to Play Key Role in Growth

ET-27

NEW DELHI Water needs to be priced well as India's economic growth will be determined by how the country manages and recycles its water, Niti Aayog CEO Amitabh Kant said Monday. Kant added that 30% of urban and 70% of rural water comes from groundwater, which is depleting rapidly. "There is sheer shortage of water... Water needs to be priced well. If not, then people won't understand its value," Kant said, addressing a 'capacity building programme on management of water' here. "India's economic growth will be determined by how we manage and recycle water," he added. Noting that 75% household don't have drinking water in their premises, he said, "India's water recycling capacity is only 30%."

News item/letter/article/editorial Published on 27.11.2018..... in the

Hindustan Times
Statesman
The Time of India (New Delhi)
Indian Express
Tribune

Hindustan (Hindi)
Nav Bharat Times (Hindi)
Punjab Keshari (Hindi)
The Hindu (New Delhi)
Rajasthan Patrika (Hindi)

Deccan Chronicle
Deccan Herald
The Times of India (A)
Business standard
The Economic Times

and documented at Bhagirath (English) & Publicity Section, CWC

A.P. is all set to become a water-surplus State: Naidu

Lays stone for Godavari-Penna river-linking project H27

P. SAMUEL JONATHAN
NAKERIKALLU

The Andhra Pradesh government has set an ambitious target of completing 62 major and minor irrigation projects before May next, Chief Minister N. Chandrababu Naidu said here on Monday.

"From the Vamsadhara project in north coastal Andhra to the Gandikota project in Kadapa district, this government has designed projects aimed at tapping every drop of water. Of the 62 irrigation projects, 17 have been completed and the rest will be completed by May-end," Mr. Naidu told a gathering of farmers.

He was laying the foundation stone for the first phase of the Godavari-Penna river-linking project here on Monday.

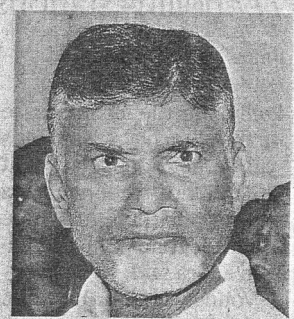

N. Chandrababu Naidu

Five phases

The project was designed to be completed in five phases at a cost of ₹83,796 crore, with the first phase beginning with the diversion of Godavari waters at Harischandrapuram and construction of a lift irrigation scheme at Nakerikallu, 80 km from Vijayawada.

The first phase would cost ₹6,020 crore and require 3,500 acres of land, which was to be acquired from farmers.

"I have set a deadline of five months for the first phase and I want land acquisition completed within three months. Farmers should get inspired by the magnanimity shown by farmers in Amaravati, who parted with 35,000 acres to facilitate the construction of a greenfield city," Mr. Naidu said. The Godavari-Penna river-linking project would be completed within two years, he added.

News item/letter/article/editorial Published on 27.11.2018..... in the

Hindustan Times
Statesman
The Time of India (New Delhi)
Indian Express
Tribune

Hindustan (Hindi) ✓
Nav Bharat Times (Hindi)
Punjab Keshari (Hindi)
The Hindu (New Delhi)
Rajasthan Patrika (Hindi)

Deccan Chronicle
Deccan Herald
The Times of India (A)
Business standard
The Economic Times

and documented at Bhagirath (English) & Publicity Section, CWC

आपदा या बड़े खतरे की दस्तक

केरल की बाढ़ के बाद तमिलनाडु के गाजा तूफान ने जलवायु परिवर्तन की आशंकाओं को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है।

चक्रवाती तूफान गाजा बीते 16 नवंबर को तमिलनाडु में नागपट्टिनम और वेदारण्यम के तटीय जिलों से टकराया, और अपने पीछे सात दशकों की सबसे बड़ी तबाही के निशान छोड़ गया। इसे 'गंभीर चक्रवाती तूफान' माना गया, जिसका अर्थ है कि हवा की गति प्रति घंटे 89 से 118 किलोमीटर थी। इसमें तेज हवा के साथ भारी बारिश भी हुई, जिससे तमिलनाडु के दर्जन भर जिले प्रभावित हुए।

इस तूफान में कम से कम 45 लोगों की जान गई और इन्फ्रास्ट्रक्चर, संपत्ति व खेती-किसानी को भारी नुकसान पहुंचा। तूफान अपने रास्ते में आने वाले सभी को उड़ा ले गया। इसमें बड़ी संख्या में मवेशी और जंगली जानवरों की मौत हुई, लाखों पेड़ धराशायी हुए, बिजली के खंभे उखड़ गए, घरों को नुकसान पहुंचा और खेतों में लगी फसलें बर्बाद हो गईं। तमिलनाडु के कावेरी 'डेल्टा क्षेत्र' में, जिसे राज्य का चावल का कटोरा कहा जाता है, तबाही के निशान और मलबे पसरे हुए हैं। एक बड़ी आबादी का पेट भरने वाले यहां के किसान आज अपनी दो जून की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

तूफान आने से पहले राज्य सरकार ने लोगों के लिए कई चेतावनियां जारी की थीं। नतीजतन, मछुआरों को गहरे समुद्र से वापस बुला लिया गया था और तटीय क्षेत्रों में रहने वाली बड़ी आबादी सुरक्षित स्थानों पर चली गई थी। इन सबसे कई जिंदगियां बच गईं। मगर जिस तरह इस तूफान ने पूरे क्षेत्र को अपने आगोश में ले लिया, वह अभूतपूर्व था। यह चक्रवाती तूफान इतना व्यापक व तीव्र होगा, इसका अंदाजा न तो सरकार को था और न ही आम लोगों को। करीब दो हफ्तों के बाद भी कई सुदूर गांवों में बिजली सेवा बहाल नहीं की जा सकी है, क्योंकि बिजली की तारें टूटी हुई हैं। मलबों से पटी गांव की सड़कें जिला मुख्यालय से अब भी कटी हुई हैं। हालांकि प्रशासन सड़कों और पुलों को बहाल करने में जुटा हुआ है।

इस तूफान से सबसे ज्यादा नुकसान नारियल के किसानों को हुआ है। रिटर्न के लिहाज से कहीं ज्यादा लाभदायक माने जाने वाले 50-70 वर्ष पुराने पेड़ उखड़कर जमीन पर लेट चुके हैं। इन किसानों को अब जल्द ही कुछ नया करना होगा, क्योंकि नए पेड़ कम से कम 10-15 साल बाद ही फल देना शुरू करते हैं। इसके अलावा, उनके सिर से छत भी छिन गई है, और पीने का पानी तक उन्हें उपलब्ध नहीं हो पा रहा। ज्यादातर किसानों ने किसी प्रकार का फसल बीमा नहीं लिया है। जाहिर है, अधिकतर किसानों की हालत गंभीर है और वे कर्ज के जाल में फंस सकते हैं, क्योंकि उनके पास पूर्व में उधार लिए गए पैसों को वापस करने के लिए कमाई का कोई साधन नहीं बचा है।

भारत के तटीय इलाके सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्र माने जाते हैं। दुनिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जितनी तूफानें आती हैं, उसकी 10 फीसदी यहीं से गुजरती हैं। इस बाबत नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट (एनसीआरएमपी) ने तमाम तरह के निष्कर्ष निकाले हैं, मगर उनमें से एक यह बताता है कि 'जलवायु परिवर्तन और इसके कारण समुद्र के जल स्तर में होने वाले बदलाव तटीय आबादी के लिए खतरा कहीं अधिक बढ़ा सकते हैं'। पिछले हफ्ते पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भी केरल को अगस्त में तबाह करने वाली अतिवृष्टि और बाढ़ पर अपना विश्लेषण जारी किया, जिसका निष्कर्ष बताता है कि राज्य के लिहाज से सदी की इस भयंकर तबाही का कारण जलवायु परिवर्तन था।

देश के दक्षिणी तटों पर लगातार आई दो आपदाओं से अब हमें चेत जाना चाहिए। राजनीतिक सत्ता प्रतिष्ठानों यानी केंद्र व राज्य सरकारों, दोनों को एक साथ बैठने की जरूरत है। वे हालात की गंभीरता को समझें और भविष्य में इस तरह की आपदाओं से निपटने के लिए जरूरी दिशा में आगे बढ़ें। बात तटीय इलाकों की ही नहीं है, हिमालय क्षेत्र, यहां तक कि मैदानी इलाकों पर भी खतरा पसर रहा है। एक अनुमान के मुताबिक, दुनिया यदि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने में कामयाब हो भी गई, तब भी इस सदी के अंत तक हिंदू-कुश पर्वतमाला पर मौजूद एक तिहाई ग्लेशियर पिघल सकते हैं।

चित्रांकन : नितेश चौधरी

दक्षिण एक्सप्रेस

एस श्रीनिवासन
वरिष्ठ पत्रकार

तमिलनाडु के राजनीतिक वर्ग ने शुरुआत में परिपक्वता दिखाई थी, मगर जैसे ही अपर्याप्त राहत कार्य की खबरें आईं, आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए। विपक्ष ने सुबाई ई पलानीसामी सरकार को इस मोर्चे पर विफल बताया। लोगों की आलोचना झेल रहे मुख्यमंत्री ने राहत व पुनर्वास के कामों के लिए केंद्र से 15,000 करोड़ रुपये की मांग की है। राज्य सरकार ने अपने तईं तत्काल राहत कार्यों के लिए 1,000 करोड़ रुपये जारी भी किए हैं। हालांकि आपात राहत उपायों के अलावा राज्य को दीर्घकालिक पुनर्वास कार्यों का बीड़ा भी उठाना होगा। इसमें राहत शिविर और अधिक संख्या में बनाने के साथ ही सरकार को चक्रवाती तूफान झेलने वाले मकान, रोड लिंक, पुल-पुलिया, नहर, नालियां, ऊंचे वाटर टैंक, संचार व बिजली आपूर्ति लाइन आदि बनाने होंगे।

हालांकि इन तमाम उपायों की एक सीमा है। सबसे जरूरी तो यही है कि जलवायु परिवर्तन की समस्या पहचानी जाए और भारत सहित तमाम देश, खासतौर से विकसित मुल्क इस पर गंभीरता से विचार करें। चूंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख नकारात्मक है और उन्होंने जलवायु से जुड़े किसी भी प्रोग्राम को फंड देने से इनकार कर दिया है, इसीलिए विश्व समुदाय उलझन में है। एक्टिविस्ट लगातार मुखर हैं कि जलवायु परिवर्तन कोई भविष्य की समस्या नहीं है, बल्कि यह बदलाव सूखे, चक्रवाती तूफान, भारी बारिश और धूल भरी आंधी के रूप में हमें आज भी नुकसान पहुंचा रहा है। मगर राजनीतिक सत्ता प्रतिष्ठान उदासीन दिखता है।

बहरहाल, अत्यधिक बढ़ती शहरी आबादी और प्राकृतिक आपदाओं की लगातार होती घटनाओं ने लोगों को भले ही जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दों के प्रति संजीदा किया हो, पर अब भी यह हमारी नीतियों या चुनावी मुद्दों में शामिल नहीं हो सका है। हालांकि तमिलनाडु के मतदाता राजनीतिक वर्गों के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए अब कहने लगे हैं कि 'अगर मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट के सदस्य वोट के लिए दर-दर घूम सकते हैं, तो आपदा राहत के लिए वे ऐसा क्यों नहीं कर सकते?' लिहाजा वक्त की मांग यही है कि राजनेता इन आवाजों को सुनें।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

News item/letter/article/editorial Published on 27.11.2018 ..... in the

Hindustan Times
Statesman
The Time of India (New Delhi)
Indian Express
Tribune

Hindustan (Hindi) ✓
Nav Bharat Times (Hindi)
Punjab Keshari (Hindi)
The Hindu (New Delhi)
Rajasthan Patrika (Hindi)

Deccan Chronicle
Deccan Herald
The Times of India (A)
Business standard
The Economic Times

and documented at Bhagirath (English) & Publicity Section, CWC

जल प्रबंधन पर नीति आयोग का मंथन

नई दिल्ली | विशेष संवाददाता

सिंगापुर की तर्ज पर भारत में भी शहरी इलाकों में जल प्रबंधन और उसके क्षमता विस्तार पर काम किया जाएगा। नीति आयोग ने शहरी इलाकों में जल प्रबंधन और क्षमता विस्तार पर मंथन के मकसद से एक वर्कशॉप का आयोजन किया। भविष्य में पानी की जरूरत को देखते हुए इस मंथन में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की म्युनिसिपल बॉडीज के भी प्रतिनिधि मौजूद रहे।

नीति आयोग का जल प्रबंधन से जुड़े मंथन का ये दूसरा फेज था। पहला फेज इस वित्त वर्ष की शुरुआत में लॉन्च किया गया था। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने पानी की क्षमता बढ़ाने को लेकर कहा कि देश में मौजूदा जल की रिसाइक्लिंग और उसे बचाने के उद्देश्य से बड़ी योजना और नीति की जरूरत है।

वहीं पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के सचिव परमेश्वरन अय्यर ने इस वर्कशॉप में कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को मिलकर काम करने की सख्त जरूरत है। इस दौरान आयोग ने जल प्रबंधन को लेकर सिंगापुर कोऑपरेशन एंटरप्राइज एंड टीएफ इंटरनेशनल के साथ करार भी किया है। करार में इस्तेमाल किए गए पानी के बेहतर संचयन पर फोकस किया गया है।

वर्कशॉप में उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मेघालय, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल राज्य क्षमता बढ़ाने के लिए खास तौर पर चुने गए हैं।

शहरी आबादी बढ़ने से पानी की खपत बढ़ी

भारत में साल 2000 के बाद शहरी आबादी में बड़ी बढ़त दर्ज की गई है। नीति आयोग के मुताबिक, 2001 में शहरी आबादी 29 करोड़ थी जो 2011 में 37.7 करोड़ पर पहुंच गई थी। इसी के साथ ही शहरी क्षेत्र में पानी के इस्तेमाल में भी बढ़त दर्ज की गई है। यही नहीं बढ़ते शहरीकरण की वजह से पाने की कमी भी देखने को मिल रही है। साथ ही जलवायु परिवर्तन के चलते भी बारिश में भी कमी दर्ज की जा रही है उसकी वजह से भी पानी की कमी देखने को मिल रही है।